मोदी के भाषण के विपरीत

ईएसआई अस्पतालों की हकीकत

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 20 जुलाई को भारतीय श्रम सम्मेलन के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर अपने उद्घाटन भाषण में प्रधनमंत्री मोदी ने ईएसआईसी को लेकर भी अपनी सरकार के कसीदे पढने में कोई कसर नहीं छोड़ी । जिस कम्प्यूटराइजेशन का काम करीब 6 वर्ष पूर्व शुरू हो चुका था, बेशक उससे किसी मज़दूर को कोई लाभ नहीं हुआ, उसे भी अपने खाते में जोड़ने से मोदी जी ने कोई परहेज नहीं किया। भाषण में मोदी जी ने बताया कि इस कम्प्यूटराइजेशन के द्वारा ईएसआई अस्पताल में आने वाले हर मज़दूर (मरीज़) का पूरा लेखा-जोखा रखा जायेगा, यानि कि उसे क्या बिमारी है तथा उसे कब-कब और क्या-क्या इलाज़ एवं दवा दी गयी। इससे मरीज़ जब चाहे और जहां चाहे अपनी जांच करवा सकता है।

लेकिन हकीकत में यह सब जुमलेबाज़ी के सिवाय कुछ भी नहीं है। कम्प्यूटर तो दूर की बात है, आज तक तो ऐसा कोई लेखा-जोखा किसी रजिस्टर तक में भी नहीं रखा जाता। स्थानीय एन एच-3 के अस्पताल में किस मरीज़ को क्या दवा लिखी गयी, क्या वास्तव में दी गयी और क्या नहीं दी गयी, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। छ:-छ: महीनों तक दवा स्टोर में नहीं आती, मरीज़ों को बाज़ार से, खरीदनी पड़ती है। बाज़ार से खरीदी इन दवाओं एवं टेस्टों का इएसआई से पुर्नभुगतान लेना मरीज़ को काफ़ी महंगा पड़ता है, इसलिये मरीज इसे छोड़ देना ही बेहतर समझते हैं। इस अस्पताल में दवा खरीदने की व्यवस्था इतनी लचर है कि सदैव आधे से अधिक दवायें समाप्त ही रहती हैं। खरीद का आर्डर तब जारी किया जाता है जब दवा खत्म हो जाय, जिसे आने में 3 से 4 माह लगते हैं।

स्वच्छता अभियान का नारा बुलंद करते हुए मोदी ने फ़र्माया कि अस्पताल में भर्ती हर मरीज़ की चादर प्रति दिन बदली जायेगी और चादर की पट्टी का रंग सप्ताह के प्रतिदिन के हिसाब से तय कर दिया गया है। यह आदेश ईएसआईसी के नवनियुक्त डीजी दीपक कुमार ने 19 जून को ही जारी कर दिये थे। चादरों के अलावा डीजी ने मरीजों के हित में अनेकों आदेश जारी किये, जिन्हें लागू करने का तिथिबद कार्यक्रम भी साथ ही बता दिया। लेकिन दुख की बात है कि डेढ माह के समय में एक भी आदेश पर अमल नहीं किया गया। आदेशों में बताये गये काम इतने कठिन भी नहीं थे जिनके करने में कोई दिक्कत आये। मसलन हर रोज़ चादर बदलना, दिन में दो बार शौचालयों का निरीक्षण करके रिपोर्ट लिखना ताकि वे साफ़ रहें। अस्पताल में जगह-जगह छाये अंधेरे को दूर करने के लिये रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था, चौबीसों घंटे टेलिफ़ोन पर तथा अस्पताल में आने वालों को किसी भी भर्ती मरीज की जानकारी देने की व्यवस्था करना। डॉक्टरों को दिखाने आये मरीज़ों को लाइन में न खड़ा होना पड़े। इसके लिये उनके बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करना आदि-आदि। ये सब तो ऐसे काम हैं जो किसी भी अस्पताल प्रशासक यानी कि एमएस को स्वत: कर लेने चाहिये। परन्तु इस अस्पताल में तो डीजी के आदेशों के बावजूद भी एक सूई भी इधर से उधर नहीं हिली।

डीजी ने अपने इन्ही आदेशों में कहा था कि अस्पताल में आये मरीज़ को किसी भी काम-टैस्ट, जांच व ऑप्रेशन आदि के लिये अस्पताल से बाहर धक्के न खाने पड़ें। उसे पर्याप्त इलाज एवं जांच आदि एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया जाय। परंतु यहां किसी के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगी। लगभग हर छोटे-मोटे काम के लिये सैंकड़ों मरीज़ों को रोज़ाना बाहर भेजा जा रहा है केवल इसलिये कि अस्पताल में आवश्यक उपकरण एवं साजो-सामान ही नहीं हैं और उन्हें खरीदने का कोई प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि डीजी के आदेशों की यहां कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोई देखने वाला नहीं। दिल्ली मुख्यालय से तो क्या शहर में तैनात आरडी (क्षेत्रीय निदेशक) ने भी कभी अस्पताल में आकर मौका-मुआयना करने की जरूरत महसूस नहीं की, जबकि डीजी ने इस बाबत स्पष्ट आदेश दिये हुए हैं।

मरीज़ों को सुविधायें उपलब्ध कराने से बचने के लिये पिछले दिनों एमएस ने ईएसआई मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी कि उनके पास मात्र 100 बेड ही इस्तेमाल में हैं, जिनके लिये अस्पताल में सब कुछ पर्याप्त है यानी कि न तो उन्हें किसी स्टाफ़ की जरूरत है न ही साजो-सामान व उपकरण आदि की। विदित है कि इसी अधिकारी ने एमसीआई को लिखित में दिया है कि यहां 300 बेड हैं। सुविधायें न होने की वजह से सैंकड़ों मरीज़ों को निजी अस्पतालों में रैफ़र किया जाता है जिस पर निगम का करोड़ों रुपया बर्बाद होता है और मरीज़ जो परेशान होते हैं वे अलग से।

डीजी के सदप्रयासों से
मेडिकल कॉलेज चलने का रास्ता साफ़ हुआ

गत 6 वर्षों से बना रहा मेडिकल कॉलेज व नया अस्पताल अब चालू होने के बहुत करीब पहुंच गया। दिनांक 29 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने ईएसआई कार्पोरेशन को कहा है कि वह शपथपत्र दायर करे कि उसने एमसीआई द्वारा बताई गयी तमाम कर्मियों को पूरा कर लिया है। वास्तव में इस तथा इस जैसे कुछ अन्य मेडिकल कॉलेजों को चलाने के लिये कमर कसे हुए डीजी दीपक कुमार पहले सुप्रीम कोर्ट गये थे जहां से उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा गया। हाई कोर्ट ने दो सप्ताह में उक्त शपथपत्र दायर करने को कहा है। इस पर संतुष्ट होने के बाद हाई कोर्ट इसी सत्र से कॉलेज को चलाने की अनुमति प्रदान कर देगी।

कल शाम को आये इस फ़ैसले के तुरन्त बाद डीजी ने कार्पोरेशन मुख्यालय के तमाम सम्बन्धित अधिकारियों को हाई एलर्ट पर कर दिया है। इस बाबत 30 जुलाई को देश भर में मौजूद तमाम सम्बन्धित अधिकारियों को डीजी ने वीडियों कान्फ्रेंस के द्वारा सम्बोधित करते हुए यहां के एमएस को भी जरूरी काम तुरन्त निपटाने के आदेश दिये हैं।

जनहित के लिये सतत प्रयासों में जुटे डीजी को समय रहते उन काली भेड़ों को भी पहचान कर उनकी गर्दन मरोड़ देनी चाहिये जो आज भी मेडिकल कॉलेज को न चलने देने के लिये षड़यन्त्र रचने में पूरे जी-जान से जुटे हैं।

विज की जासूसी कपूर की मायूसी

फ़रीदाबाद (म.मो.) हरियाणा के स्वास्थ्य मन्त्री अनिल विज की जासूसी करता सीआईडी का एएसआई खुद विज ने ही रंगे हाथों पकड़ लिया। समाचारों के अनुसार सीआईडी का वह एएसआई प्रतिदिन विज के दफ़्तर के सामने आकर बैठ जाता था और विज के पास हर आने-जाने वाले का नाम डायरी में लिखता रहता था। उधर विज भी कई दिनों से इस एएसआई पर नज़र रखे हुए थे और एक दिन उसे पकड़ कर अपने दफ़्तर में बैठा लिया। डायरी चैक की तो सारी बात विज की समझ में आ गयी। पूछताछ करने पर एएसआई ने स्वीकार किया कि उसको इस ड्यूटी पर लगाया गया था।

दरअसल किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की जासूसी कराना कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री अपने तमाम विधायकों एवं मन्त्रियों पर नज़र रखने के लिये सीआईडी विभाग का इस्तेमाल करता है। कहने को बेशक सीआईडी का अर्थ आपराधिक जांच विभाग है, परन्तु आपराधिक जांच से इसका अब कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं रह गया है। करोड़ों रुपये के बजट वाले इस विभाग की हर ज़िले में एक इकाई तैनात है। दिल्ली में भी इसकी एक बड़ी इकाई है। चंडीगढ स्थित मुख्यालय में तो अफ़सरों का भारी जमावड़ा है। अफ़सरों के वेतन भत्तों के अलावा सैंकड़ों वाहनों का बेड़ा इन्हें मुहय्या करा रखा है। इसके अलावा मुखबिरों से सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिये भी इनके पास पर्याप्त नकदी रहती है जिसका किसी को हिसाब नहीं देना होता।

जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वह सबसे पहले एक अच्छे समझदार काबिल एवं विश्वसनीय पुलिस अफ़सर को अपना सीआईडी प्रमुख चुनता है। मनोहर लाल खट्टर ने भी शत्रुजित कपूर के रूप में अपनी पसंद का सीआईडी प्रमुख चुन लिया। कपूर की एक ही खूबी इस पद के लिये प्रर्याप्त थी कि वह कपूर हैं। यानी खट्टर की तरह ही एक पंजाबी। यदि उनमें थोड़ी सी भी पेशेवाराना बुद्धि होती तो वे इस तरह से अपने किसी आदमी को मन्त्री के दरवाजे पर न बैठने देते। इनसे पहले के सीआईडी प्रमुख भी तो तमाम विधायकों व मन्त्रियों की पूरी जासूसी करते रहे हैं, लेकिन कभी इस कदर चौड़े में नंगे नहीं हुए। कुशल अफ़सर इस काम के लिये बाकायदा सूत्रों को विकसित करते हैं जो उन्हें समय-समय पर सटीक जानकारियां उपलब्ध करायें।

सीआईडी विभाग के अलावा भी कपूर का पुलिसिंग रिकार्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। झूठे एवं बेबुनियाद मुकदमों में बेगुनाहों को लपेटना इनका शौक रहा है। बतौर आईजी हिसार तो इन्होंने एक एचसीएस अधिकारी को ही झूठे मुकदमे में लपेट दिया था। पुलिस कमिश्नर फ़रीदाबाद की तैनाती के दौरान एक पत्रकार एक सरकारी वकील व एक नागरिक को भी झूठे बेबुनियाद मामले में लपेटा गया। और तो और दो बेगुनाह दिहाड़ीदार मज़दूरों को ऐसे कत्ल केस में लपेट दिया था जो उन्होंने किया ही नहीं था। इससे भी बड़ी बात तो यह थी कि असली कातिल के पकड़े जाने के बावजूद कपूर ने उन बेगुनाहों को अदालत से डिस्चार्य नहीं कराया, उन्हीं पर कत्ल का मुकदमा अन्तिम बहस तक पहुंचने दिया। शुक्र यह हुआ कि कुछ संवेदनशील पुलिसकर्मियों की सहायता से 'मज़दूर मोर्चा' ने उस केस का रहस्योद्घाटन कर दिया। उस पर तत्कालीन जज दर्शन सिंह ने बेगुनाहों को बरी किया तथा दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाही के आदेश दिये।

इस तरह के अनेकों मामले हैं जिनसे कपूर की 'गुणवत्ता' के स्तर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और साथ ही खट्टर की अपनी समझ का भी।

मोदी के इन्तज़ार में खडी मैट्रो करोड़ों का घाटा व जनता परेशान

फ़रीदाबाद (म.मो.) 12 मार्च 2012 को मैट्रो रेल कार्पोरेशन ने यहां साढे 13 किलोमीटर लम्बी लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया था। हरियाणा सरकार के तमाम नाकारा विभागों से जूझते हुए कार्पोरेशन ने इस माह अपना काम पूरी तरह से निपटा दिया है। सारे ट्रायल कामायाबी के साथ पूरे कर लिये हैं। इसके बावजूद 2 लाख से अधिक यात्री अपने सफ़र को सुखद बनाने के लिये अब भी इसके चालू होने का इन्तज़ार कर रहे हैं। जनता को यह इन्तज़ार इसलिये कराया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को या तो अभी जुमलेबाज़ियों से फ़ुर्सत नहीं या फ़िर ज्योतिषियों ने अभी इसको हरी झंडी दिखाने का शुभ मुहुर्त नहीं निकाला।

चर्चा यह भी उछाली जा रही है कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मोदी जी शहर को यह तोफ़ा भेंट करेंगे। वैसे मोदी जी का इस तोफ़े से कोई मेल तो है नहीं और न ही इस परियोजना में उनका कोई योगदान रहा है। कुल 2600 करोड़ की लागत से बनी यह लाइन पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी। इसकी कुल लागत में से करीब 500 करोड़ हरियाणा की जनता द्वारा दिये गये टैक्स से और शेष पैसा केन्द्र सरकार तथा रेल कर्पोरेशन के खातों से आया है। इस सारे खेल में मोदी की भूमिका तो कहीं दूर-दूर तक नज़र नहीं आती। इस देश में तमाम पार्टियों के नेताओं को यह बड़ा भारी भ्रम है कि परियोजनाओं का शिलान्यास अथवा उद्घाटन करके वे जनता को अपने अहसान तले दबा लेते हैं। जनता सब समझती है कि ये सारी परियोजनायें उनके खून पसीने की कमाई से ही बनती हैं, नेता तो केवल उनमें से अपना मोटा कमीशन डकारते हैं।

मोदी या कोई नेता इस रेल को हरी झंडी न भी दिखाये तो भी यह रेल सही सलामत चल कर जनता को राहत पहुंचा सकती है। सुरक्षा आयुक्त की जांच का बहाना बना कर इसे बेजातौर पर रोके रखने से जहां यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है वहीं इस खेल से रेल कार्पोरेशन को भी बीसियों लाख का घाटा प्रतिदिन हो रहा है। लेकिन जनता के हितों को दरकिनार कर केवल अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने वालों को इन सबसे क्या लेना।

पद पावन की दौड़ में जीती सीमा, स्वागत में उमड़ी जनता

फ़रीदाबाद (म.मो.) जिस फ़रीदाबाद-पलवल ज़िले से कभी 4-4 मन्त्री हरियाणा मन्त्रिमंडल में रहे हों उस ज़िले से अभी तक एक भी मन्त्री खट्टर मन्त्रिमंडल में जगह नहीं ले पाया था। इस जगह को पाने के लिये क्षेत्र के मात्र 3 ही विधायक दौड़ में थे क्योंकि बाकी 6 तो गैर भाजपाई हैं। अत: ये तीनों-सीमा त्रिखा, विपुल गोयल और मूलचंद शर्मा-ही मन्त्रिमंडल में घुसने के लिये एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाये हुए थे। साम-दाम दण्ड भेद से भी किसी को कोई परहेज नहीं था। कहने को ये तीनों जनता, खासकर गरीबों की सेवा करने के लिये पद की दौड़ में थे।

खैर मन्त्री पद तो किसी को नसीब नहीं हुआ। हां, मुख्य संसदीय सचिव के रूप में एक छोटा सा टुकड़ा मनोहर लाल खट्टर ने सीमा त्रिखा को जरूर फ़ेंक दिया है। जिसे पाकर न केवल वे अति प्रसन्न हैं बल्कि, मीडिया की मानें तो सारा शहर खुशी के हिलोरे मार रहा है। इस व्यवस्था में वैसे तो मन्त्री के पल्ले भी कुछ खास नहीं होता, जो कुछ होता है वह मुख्यमंत्री के हाथ में ही होता है परन्तु मुख्य संसदीय सचिव के पल्ले तो छोड़ा ही कुछ नहीं जाता। हां झंडी वाली बड़ी से कार, चंडीगढ में कोठी, सचिवालय में छोटा-मोटा दफ़्तर व स्टाफ़ तथा पुलिस का सुरक्षा घेरा जरूर मिल जाता है। सीमा को तो कार भी वही दी गयी बताते हैं जो बतौर कैबिनेट मन्त्री महेन्द्र प्रताप सिंह के पास थी। क्योंकि उन्हें चुनाव में बुरी तरह पछाड़ने का श्रेय सीमा त्रिखा के खाते में दर्ज है।

इस उपलब्धि से सीमा त्रिखा के खुश होने की बात तो समझ में आती है क्योंकि इससे उनका राजनीतिक व सामाजिक कद तो बढा ही है आर्थिक लाभ भी ठीक-ठाक हो तो ताज्जुब नहीं। सभी नेताओं को होता है। परन्तु खुशी के हिलोरे मारती जनता को ऐसा कौनसा लाभ होने जा रहा है जो गत 7-8 माह से खट्टर सरकार ने नहीं दिया अथवा पूर्व मन्त्रियों महेन्द्र प्रताप, ए सी चौधरी, शिवचरण लाल शर्मा, शरदा राठौरा व शारदा रानी नहीं दिला पाये?

जनता को शायद खुशफहमी हो सकती है कि सीमा के बनने से अगली बरसात में शहर की सड़कों पर जलभराव न हो, तमाम मैनहोल के ढक्कन लग जायें, सीवरेज की गंदगी सड़कों पर बहनी बंद हो जाय, रात के अंधेरे में सड़कों पर बने गड्ढों में गिरने से निजात मिल जाय, पीने का पानी मिलने लग जाय आवारा पशुओं कुत्तों व बंदरों से निजात मिल जाये। सड़कों पर अवैध कब्ज़े व अवैध निर्माणों से शहर को बचाया जा सके।

शहर के अस्पतालों में आम जनता को दुर्गति से बचाने के लिये पर्याप्त स्टाफ़ एवं आवश्यक साज़ो सामान, उपकरण व दवायें उपलब्ध हो जायें। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल के दरबाजे पर बच्चे न जनने पड़ें।

स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में पढे लिखे शिक्षक हो जायेंगे, विद्यार्थियों के बैठने, पेयजल तथा शौचालय की व्यवस्था हो जाय। मैट्रो मोड़ स्थित सरकारी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की एक साल से टूटी चारदिवारी ठीक हो जाय।

बसें पर्याप्त मात्रा में व समय पर चलने लगें, राशन डिपो की धांधली बंद हो जाय, पुलिस एवं कानून व्यवस्था सुधर जाये। तहसील, नगर निगम व हूडा कार्यालय भ्रष्टाचार से मुक्त हो जायें।

जनता को इस तरह की खुशफहमी पालने का पूरा अधिकार है, हो भी क्यों न जब पहले से पालते आ रहे हैं तो अब क्यों न पालें?

खुश होकर उछलने-नाचने, यहां तक कि इस काम के लिये चंडीगढ तक पहुंचने वालों में अधिकांश चेहरे वही नज़र आ रहे थे जो पहले महेन्द्र प्रताप के चक्कर लगाते थे। ये लोग पहले महेन्द्र प्रताप के 'घर के आदमी' होते थे अब वे सीमा के 'घर के आदमी' हो गये हैं और कल को किसके 'घर के आदमी' होंगे समय ही बतायेगा। दरअसल इन सदाबहार चापलूसों का कारोबार ही किसी न किसी के 'घर का आदमी' बने रहने से चलता है।